



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 23 अप्रैल, 2004/3 बैशाख, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

पधिसूचना

शिमला, 12 अप्रैल, 2004

संख्या एच० पी० डी० आर० सी०.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 43 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्ति की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव संहित, जो इस बाबत उक्त अधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कार्मिशियल कॉम्प्लेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

### प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत प्रदाय करने का कर्तव्य) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम, हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके अनुज्ञात क्षेत्रों में लागू होंगे।

(3) ये विनियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो आयोग अधिनूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यायनिर्णयन अधिकारी” से आयोग का वह सदस्य अभिप्रेत है जिसे आयोग उन मामलों का, जिनके लिए अधिनियम में उस द्वारा न्यायनिर्णयन करना विनिर्दिष्ट किया गया है, न्यायनिर्णयन करने के लिए नियुक्त करता है;

(ग) “आवेदक” से परिसर का स्वामी या अधिभोगी, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय के लिए आवेदन देता है, अभिप्रेत है;

(घ) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) “अतिरिक्त उच्च टेन्शन (EHT) उपभोक्ता” से वह उपभोक्ता जिसे 33000 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है;

(च) “उच्च टेन्शन (HT) उपभोक्ता” से वह उपभोक्ता जिसे 440 वोल्ट से अधिक और 33000 वोल्ट से अनाधिक वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है;

(छ) “न्यून टेन्शन (LT) उपभोक्ता” से वह उपभोक्ता, जिसे 440 वोल्ट तक की वोल्टता पर विद्युत प्रदाय की जाती है, अभिप्रेत है;

(ज) “माह” से कलैण्डर मास अभिप्रेत है तथा बिलों के प्रयोजन के लिए दो क्रमवर्ती मीटर रीडिंग में आने वाली लगभग 30 दिन की अवधि एक माह समझी जायेगी; तथा

(झ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः नियत किया गया है।

3. अनुरोध पर प्रदाय करने का कर्तव्य.—(1) किसी परिसर स्वामी या अधिभोगी से आवेदन प्राप्त के उपरान्त, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आवेदक को, रजिस्टर्ड डक/स्पीड पोस्ट द्वारा मांग नोटिस, स्पष्टतया निम्नलिखित दर्शित करते हुए, भेजेगा, अर्थात्—

(क) आवेदक द्वारा पूरी की जानी वाली कमी तथा औपचारिकताएं;

(ख) अनुमादित वार्षिक ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट देने की आवश्यकता;

(ग) आवेदक द्वारा संदत किये जाने वाले प्रभार तथा प्रतिभूति रकम:—

मांगे गए सर्विस कुनैक्शन की किस्म

आवेदन प्राप्ति से कालावधि जिसके भीतर मांग नोटिस भेजा जाना चाहिए।

न्यून टैन्शन (LT) स्पलाई

10 दिन

11 के० वी० स्पलाई

15 दिन

22 के० वी० स्पलाई

15 दिन

33 के० वी० स्पलाई

30 दिन

अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) स्पलाई

60 दिन

(2) आवेदक द्वारा, उपविनियम (1) में दर्शित, कमियों को दूर करने तथा औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रभार तथा प्रतिभूति रकम का संदाय करने पर, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विद्युत प्रदाय करेगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी परिसर को विद्युत प्रदाय:—

(क) यहां ऐसे प्रदाय में मुख्य तारों का विस्तार करना, या नया उप-केन्द्र आरम्भ करना अपेक्षित नहीं है वहां उप-विनियम (1) के मांग नोटिस में बताई गई औपचारिकताएं पूर्ण होने तथा प्रभारों तथा प्रतिभूति रकम के संदाय से 20 दिनों के भीतर करेगा,

(ख) यहां ऐसे प्रदाय में मुख्य तारों का विस्तार करना या नए उपकेन्द्र आरम्भ करना अपेक्षित है, परन्तु नया 33/11 के० वी० उप-केन्द्र स्थापित करना या आरम्भ करना आवश्यक नहीं है, तो निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेगा है:—

मांगे गए सर्विस कुनैक्शन की किस्म

मांग नोटिस में दर्शित औपचारिकताओं के पूरा होने से कालावधि जिसके भीतर विद्युत प्रदाय किया जाना है।

न्यून टैन्शन (LT) स्पलाई

40 दिन

11 के० वी० स्पलाई

30 दिन

22 के० वी० स्पलाई

30 दिन

33 के० वी० स्पलाई

60 दिन

अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) स्पलाई

120 दिन

परन्तु विनिर्दिष्ट मामलों में यहां विस्तार इतने बड़े पैमाने पर अपेक्षित है कि अनुज्ञप्तिधारी को इसमें अधिक समय दरकार है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से, अवधि बढ़ाने के दावे के समर्थन में बौरे प्रस्तुत करते हुए, उपरिविनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकेगा और यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए गए व्यौरे के औचित्य से आयोग सन्तुष्ट हो जाता है तो आयोग विद्युत प्रदाय आरम्भ करने की अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(ग) नये कनेक्शन के लिये आवेदन की दशा में यहां प्रदाय के लिए नया 33/11 के० वी० उप-केन्द्र स्थापित करना तथा आरम्भ करना आवश्यक है वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर, आयोग को, 33/11 के० वी० उपकेन्द्र के स्थापित करने का, उसके आरम्भ करने में लगने वाले अपेक्षित कालावधि का उल्लेख करते हुए, प्रस्ताव भेजेगा। आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा सम्बन्धित आवेदक की सुनवाई के उपरान्त, प्रस्ताव पर, तथा उप-केन्द्र की स्थापना पर लगने वाले समय के बारे में, विनिश्चय करेगा। वितरण

अनुज्ञप्तिधारी, उप केन्द्र स्थापित और आरम्भ करेगा तथा आवेदक को, आयोग द्वारा अनुमोदित कालावधि के भीतर, विद्युत प्रदाय करेगा :

परन्तु यदि उप-केन्द्र की स्थापना केवल एक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने के लिये है तो अनुज्ञप्तिधारी, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, आवेदक से आवश्यक प्रतिभूति प्राप्ति के उपरान्त ही उप-केन्द्र की स्थापना आरम्भ कर सकेगा ।

परन्तु यह और कि यहां आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में उप-केन्द्र की स्थापना समाविष्ट है तो विवरण अनुज्ञप्तिधारी उपकेन्द्र की स्थापना उक्त विनिधान योजना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ही पूरा करेगा ।

(4) यदि मार्गधिकार, भू अर्जन से सम्बन्धित समस्याओं के कारण या उपभोक्ता द्वारा उच्च-टैन्शन या अतिरिक्त उच्च-टैन्शन यन्त्रों को लगाने के लिये मुख्य विद्युत निरीक्षक की अनुमति लेने में देरी के कारण या ऐसे अन्य कारणों से, जो अनुज्ञप्तिधारी के, युक्तियुक्त नियन्त्रण से परे हैं, विद्युत प्रदाय में देरी होती है तो अनुज्ञप्तिधारी उस देरी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

(5) उपरोक्त के अधधीन रहते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि में अपेक्षित अतिरिक्त उच्च टैन्शन (EHT) विद्युत प्रदाय, जो कि 33 के 0 वी 0 से अधिक हो, उपलब्ध होगी, सम्बन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ आवश्यक वाणिज्य समझौते करना वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उत्तरदायित्व होगा ।

(6) ऐसे गांव या पुरवा या क्षेत्र, जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, के परिसरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में समाविष्ट बस्तियों के विद्युतीकरण कार्यक्रमानुसार, ऐसी अवधि जैसी आयोग द्वारा अनुमोदित विनिधान योजना में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर विद्युत प्रदाय करेगा ।

4. व्यक्तिक्रम के दुष्परिणाम.—(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो विद्युत प्रदाय हेतु विनियम 3 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसी शास्ति से दण्डनीय होगा जो आयोग के न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा(3) के अनुसार विनिश्चित की जाए ।

(2) इन विनियमों के अधीन व्यक्तिक्रम, यदि कोई हो, के लिए आरोपित की जाने वाली शास्ति, व्यक्ति व्यक्ति को अधिनियम की धारा 57 की उप-धारा (2) के अधधीन अधिसूचित विनियमों के अधीन देय प्रतिकर के दायित्व से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त नहीं करेगी ।

5. अपरिहार्य घटना.—यहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत प्रदाय करने में, चक्रवात, बाढ़, तूफान या उसके नियन्त्रण से परे अन्य घटनाओं के कारण निवारित हो जाता है, वहां विनियम 3 में विनिर्दिष्ट कालावधि लागू नहीं होगी ।

6. निर्वचन.—इन विनियमों के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवादक, आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे तथा उन विवादकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

अदेश व दिशानिर्देश जारी करना.—अधिनियम तथा इन विनियमों के अधधीन रहते हुए, आयोग उन मामलों में, जिन्हें लिये ये विनियम आयोग को निदेश देने के लिये सशक्त करते हैं, समय-समय पर, विनियमों के अनुपालन में तथा विभिन्न विषयों में प्रक्रिया अपनाने हेतु एवं प्रासंगिक या आनुषांगिक विषयों पर आदेश तथा पद्धति निदेश दे सकेगा ।

8. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इन विनियमों में किसी भी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी कार्रवाई, जो विद्युत अधिनियम 2003 के असंगत न हो और आयोग को कठिनाईयां दूर करने के उद्देश्य से समचीन लगती हो, कर सकेगा अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को करने के लिए कह सकेगा।

† (2) अधिनियम में उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग, किसी भी समय, आदेश द्वारा, इन विनियमों के उपबन्धों में परिवर्धन, उपासन्त्रण व संशोधन कर सकेगा।

(3) अधिनियम में उपबन्धों के अध्वधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा पटल पर रखा जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidyut Viniyamak Ayog (Anurodh per Anugayapatidhari ka Viduyat Parday karne ka Kartavya) Viniyam, 2004, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

### NOTIFICATION

Shimla, the 12th April, 2004

★ No. HPERC/ .—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 181, read with Sub-section (1) of section 43, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

### DRAFT REGULATIONS

1. *Short title extent and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Licensee's Duty for Supply of Electricity on Request) Regulations, 2004.

(2) These Regulations shall be applicable to all distribution licensees in their respective licensed areas, in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from such date as the Commission may, by notification appoint.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) "adjudicating officer" means any Member of the Commission appointed by the Commission to adjudicate on matters specified under the act to be adjudicated by him;
- (c) "applicant" means the owner or occupier of any premises who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity;
- (d) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (e) "extra high tension (EHT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage higher than 33000 volts;
- (f) "high tension (HT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage higher than 440 volts; but not exceeding 33000 volts;
- (g) "low tension (LT) consumer" means a consumer who is supplied electricity at a voltage upto 440 volts;
- (h) "month" means the calendar month and the period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for purpose of billing; and
- (i) The words and expressions used, and not defined, in these regulations but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. *Duty of licensee to supply on request.*—(1) On the receipt of an application from the owner or occupier of the premises, every distribution licensee shall, within the time frame specified hereunder, issue, by a registered post/speed post, a demand notice to the applicant, clearly indicating:—

- (a) all deficiencies to be made good and the codal formalities to be completed by the applicant;
- (b) necessity to furnish the test report from the approved Wiring Contractor;
- (c) the exact amount of charges and security to be deposited by the applicant—

Type of service connection requested	Period from date of receipt application within which demand notice should be issued
Low Tension (LT) supply	(10) days
11 KV supply	(15) days
22 KV supply	(15) days
33 KV supply	(30) days
Extra High Tension (EHT) supply.	(60) days

(2) Every Distribution Licensee shall, upon the applicant making good the deficiencies and completion of codal formalities and payment of charges and security, as indicated in the demand notice under sub-regulation (1), give supply of electricity to the premises within the time specified in sub-regulation (3).

(3) The Distribution Licensee shall give supply of electricity to the premises—

- (a) where no extension of distribution main or commissioning of new sub-station is required for effecting such supply within twenty days reckoned from the completion of the codal formalities and the payment of charges and security amount stated in the demand notice under sub-regulation (1);
- (b) in cases where such extension of distribution main or commissioning of new sub-station is required but there is no requirement of erecting and commissioning a new 33/11kV sub-station within the time frame specified hereunder :—

Type of service connection requested	Period from date of completion of codal formalities required vide demand notice, within which supply of electricity should be provided.
Low Tension (LT) supply	(40) days
11 KV supply	(30) days
22 KV supply	(30) days
33 KV supply	(60) days
Extra High Tension (EHT) supply	(120) days

Provided that the Distribution Licensee may approach the Commission for extension of the time specified above, in specific cases where the magnitude of extension is such that the Licensee will require more time, duly furnishing the details in support of such claim for extension and if satisfied with the justification given by the Distribution Licensee, the Commission may extend the time for commencing the supply;

- (c) in the case of application for new connection, where extension of supply requires erection and commissioning of new 33/11 KV sub-station, the Distribution Licensee shall, within 15 days of receipt of application, submit to the Commission a proposal for erection of 33/11 KV sub-station together with the time required for commissioning the sub-station. The Commission shall after hearing the Distribution Licensee and the applicant concerned, decide on the proposal and the time frame for erection of the sub-station. The Distribution Licensee shall erect and commission the sub-station and commence power supply to the applicant within the period approved by the Commission:

Provided that if the sub-station is meant to extend supply to an individual consumer, the Licensee may, unless otherwise directed by the Commission, commence erection of the sub-station only after receipt of necessary security from the applicant:

Provided further that, where such sub-station is covered in the investment plan approved by the Commission, the Distribution Licensee shall complete the erection of such sub-station within the time period specified in such investment plan.



(4) The Distribution Licensee shall not be responsible for the delay, if any in extending the supply, if the same is on account of problems relating to right of way acquisition of land, or the delay in consumers obligation to obtain approval of the Chief Electrical Inspector for his High Tension or Extra High Tension installation, or for any other similar reasons beyond the reasonable control of the Distribution Licensee.

(5) Subject to the above it shall be the responsibility of the Distribution Licensee to have necessary commercial arrangements with the respective Transmission Licensee(s) to ensure that the required supply at Extra High Tension (EHT), i. e. above 33 KV, is made available within the time frame specified under sub-regulation (2).

(6) In cases where the village or hamlet or area is not electrified earlier, the Distribution Licensee shall give supply of electricity to premises in such village or hamlet or area as per the programme of electrification of habitations covered in the investment plan approved by the Commission, within the time frame specified in such investment plan approved by the Commission,

4. *Consequences of default.*—(1) The Distribution Licensee who fails to comply with the time frame for supply of electricity stipulated in regulation 3 shall be liable to pay penalty as may be decided by the adjudicating officer of the Commission in accordance with sub-section (3) of section 43 of the Act.

(2) The liability to pay penalty under these Regulations for default if any, shall not absolve the Distribution Licensee from the liability to pay compensation to the affected person as per the regulations notified under sub-section (2) of Section 57 of the Act.

5. *Force Majeure.*—The time frame specified in regulation 3 shall not be operative where the Distribution Licensee is prevented from giving supply of electricity on account of cyclones, floods, storms and other occurrences beyond his control.

6. *Interpretation.*—All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

7. *Issue of orders and practice directions.*—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of this Regulation and procedure to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by this regulation to direct and matters incidental or ancillary thereto.

8. *Power to remove Difficulties.*—(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order take suitable action or direct the Distribution Licensee to take such suitable action, not being inconsistent with the Electricity Act, 2003, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulties.

(2) Subject to the provisions of the Act, the Commission may by an order, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

(3) Every order made this regulations shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

BY ORDER OF THE COMMISSION,

Sd/-  
Secretary.